



वित्त मंत्रालय

“हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम” के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 36 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए यह समझौता सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और कर प्रशासन की दक्षता में सुधार करेगा

Posted On: 31 MAY 2017 3:10PM by PIB Delhi

“हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम” के लिए भारत ने 36 मिलियन अमरीकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ नई दिल्ली में आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव (एमआई) श्री राज कुमार और विश्व बैंक (भारत) की ओर से कंट्री निदेशक श्री जुनैद कमल अहमद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्यान्वयन संस्था समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी और विश्व बैंक की ओर से कंट्री निदेशक (भारत) ने हस्ताक्षर किए।

इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और कर प्रशासन व्यवस्था की दक्षता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम से मुख्य विभागों, बजट की विश्वसनीयता में सुधार, राजकोषीय अनुशासन की व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने, राजकोषीय स्थिति बढ़ाने के लिए राजस्व प्रशासन में सुधार और मानव संसाधन सुधार सहित लक्षित सांगठनिक सुधारों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम योगदान देने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ की गई कार्यशालाओं में व्यक्त एवं चिन्हित किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करता है। इस कार्यक्रम पर कुल 45 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है, इसमें से 36 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, बकाया धनराशि का प्रबंधन राज्य के बजट से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पूरा होने की अवधि पांच वर्ष है।

जीवाई/प्रवीन - 1568

(Release ID: 1491511) Visitor Counter : 8

